

यूप्लेक्स ने कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के लिए की क्रेड्यूस के साथ साझेदारी

2024 के अंत तक लगभग
175,000 टन कार्बन उत्सर्जन
को कम किया जाएगा



नोएडा। भारत को 2070 तक देश को कार्बन नेट जीरो बनाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता से देश का कॉरपोरेट नेतृत्व बहुत उत्साहित है। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, अपने-अपने क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी दो कंपनियों ने इस सपने को साकार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्लेक्सिबल पैकिंग सामग्री और समाधान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी 'यूप्लेक्स' ने भारत की सबसे तेजी से बढ़ती कार्बन क्रेडिट कंसलटेंसी 'क्रेड्यूस' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इसे अपना सलाहकार भागीदार बनाया

ताकि एंड-टू-एंड कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल की जा सके। इसके अंतर्गत कार्बन फुटप्रिंट और न्यूट्रैलिटी को समझना और उसका विश्लेषण करना होगा, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत और मान्यता प्राप्त मंच पर कार्बन और प्लास्टिक क्रेडिट बैलेंस बनाया जाएगा और उसे औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह स्थायी विकास लक्ष्य का भाग होगा जिसमें सस्टेनेबिलिटी के लिए रोडमैप बनाने के साथ- साथ और

भी बहुत कुछ किया जाएगा। सामाजिक रूप से जिम्मेदार एक कॉरपोरेशन के रूप में, यूप्लेक्स आधुनिक टेक्नोलॉजी से संचालित समाधान बनाने में अग्रणी रहा है। यूप्लेक्स के महाप्रबंधक- एचआर एवं सस्टेनेबिलिटी, मानस कुमार सरकार कहते हैं, सामाजिक पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी पिछले कुछ समय से हमारे मुख्य संगठनात्मक मूल्यों में से एक रहा है और हमने हमेशा अपने कामकाज

के सभी क्षेत्रों में इसे व्यक्त और आत्मसात किया है। यूप्लेक्स में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस के ज्वाइंट प्रेसिडेंट जीवराज पिहर्ड का कहना है, हम हमेशा अपने समूह को स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थे, हम पूरे समूह में वर्ष 2024 के अंत तक लगभग 175,000 टन कार्बन उत्सर्जन के बराबर कटौती करना चाहते हैं। क्रेड्यूस के निर्देशक शैलेन्द्र सिंह राव कहते हैं, क्रेड्यूस में हम यूप्लेक्स जैसे संगठनों के बीच कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अपार संभावनाएं देखते हैं। हम नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में एक रणनीति बनाने में सक्षम होंगे। ऐसे कदम जो सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाएंगे।